

देश भर में फैली अपनी सम्पत्तियों को समेटना चाहती है, कांग्रेस पार्टी

एआईसीसी में इंदर सिंह सिंगला की अध्यक्षता में एक अलग विभाग का गठन किया गया है, इस मकसद से। सिंगला एआईसीसी में फिलहाल जॉइन्ट कोषाध्यक्ष भी हैं

-रेणु मित्तल-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 5 मार्च। एआईसीसी ने देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में फैली अपनी सम्पत्तियों को समेटने (कन्सॉलिडेशन) का काम शुरू कर दिया है। इनमें से बहुत सी सम्पत्तियाँ जिला-स्तर पर हैं तथा इनमें से कई सम्पत्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि पिछले अनेक वर्षों में, विभिन्न संगठनों और प्रतिष्ठानों ने उन पर गैर-कानूनी रूप से कब्जे कर लिये हैं।

इन सम्पत्तियों के सम्बंध में अदालतों में केस दायर करने तथा उन्हें एआईसीसी के अधिकार में लेने की प्रक्रिया करीब 3 साल पहले शुरू हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस ने इन सम्पत्तियों की व्यवस्था एवं देख-रेख के लिये एआईसीसी में एक पृथक विभाग बना दिया है तथा इंदर सिंह सिंगला, जो एआईसीसी के संयुक्त कोषाध्यक्ष भी हैं, इस विभाग के प्रमुख बनाये गये हैं। इंदर सिंह सिंगला का पंजाब

■ सिंगला सांसद, विधायक व मंत्री भी रह चुके हैं, पंजाब में। सिंगला पर हाईकमान का पूरा विश्वास है तथा राज्यों में पार्टी के विभिन्न नेताओं को चुनाव के लिये पैसे भेजने का काम सिंगला चुपचाप कई वर्षों से कर रहे हैं।

■ अतः, अब कांग्रेस पार्टी की देश में स्थित सम्पत्तियों पर चल रहे मुकदमों को न्यायालय में छोड़ना तथा पार्टी की सम्पत्तियों के रख-रखाव व मरम्मत आदि की जिम्मेवारी, सिंगला पर लड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

■ अब तक इन सम्पत्तियों की देखभाल का काम राहुल के करीबी माने जाने वाले कनिष्क सिंह देख रहे थे। पर, अब एआईसीसी में एक नया विभाग बनाकर, यह जिम्मेवारी इस विभाग को सौंपना इस बात का प्रमाण है कि, अब कांग्रेस पूर्णतया गंभीर है, अपनी सम्पत्तियों का कब्जा ग्रहण कर तथा न्यायालय में इन प्रॉपर्टीज के मुतल्लिक चल रहे मुकदमों को जीतकर एक ही जगह संगठित करने के बारे में।

में अच्छा-खासा नैटवर्क है। वे पंजाब से सांसद, विधायक एवं मंत्री भी रहे हैं। उनके दायित्वों में उन राज्यों तथा वहाँ के पार्टी नेताओं को चुपचाप धनराशि भेजना भी शामिल है, जहाँ चुनाव होने वाले होते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वे इस काम को चुपचाप तथा पूरी निपुणता के साथ

जयपुर, 5 मार्च। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को विधायक अमीन कागज़ी ने राजधानी जयपुर की प्रसिद्ध एम आई रोड का मामला उठाया, जो टूटी-फूटी पड़ी है। कागज़ी ने शून्यकाल में स्थान प्रस्ताव के तहत यह

क्षतिग्रस्त एम.आई. रोड

जयपुर, 5 मार्च। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को विधायक अमीन कागज़ी ने राजधानी जयपुर की प्रसिद्ध एम आई रोड का मामला उठाया, जो टूटी-फूटी पड़ी है। कागज़ी ने शून्यकाल में स्थान प्रस्ताव के तहत यह

■ राशि जमा होने के बाद भी मरम्मत नहीं?

मामला उठाते हुए राज्य सरकार से एम आई रोड एवं जौहरी बाजार की टूटी सड़कों की मरम्मत कराने का आग्रह किया, ताकि इन मुख्य बाजारों में लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

उन्होंने कहा कि दो साल पहले ही एम आई रोड पर काम हुआ था, लेकिन पेयजल पाइप लाइन डालने के लिए अजमेरी गेट से लेकर गवर्मेन्ट हॉस्पिटल तक सड़क को खोद दिया गया है और अब सड़क को मरम्मत के लिए संबंधित विभाग की तरफ से राशि जमा करा देने के बावजूद, इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

लखनऊ अदालत ने राहुल गांधी पर 200 रु. जुर्माना लगाया

लखनऊ, 05 मार्च। राजधानी लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उन पर यह कार्रवाई लगातार पेशी से गायब रहने पर की है। चेतावनी दी है कि 14 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर हों। इस तारीख को अगर राहुल गांधी पेश नहीं होते हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 दिसंबर 2022 को वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। वीर सावरकर

■ यह जुर्माना लगातार पेशी से गायब रहने पर लगाया गया है।

को राहुल गांधी ने अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला बताया था। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की, जिसमें बताया गया कि आज, यानी 5 मार्च को राहुल गांधी पूर्व निर्धारित एक विदेशी अतिथि से मुलाकात में व्यस्त होने के चलते कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हल्के में न लेते हुए उन पर 200 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया और 14 अप्रैल को हर हाल में पेश होने का आदेश दिया।

‘राजीव गांधी शिक्षा की दृष्टि से काफी पैदल थे’

मणि शंकर अय्यर ने एक वीडियो जारी कर यह अजीबो-गरीब टिप्पणी की तथा यह भी कहा कि वे दो बार फेल हुए थे, पहले कैम्ब्रिज में और फिर दोबारा इम्पीरियल कॉलेज लंदन में।

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मार्च। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने स्वर्गीय राजीव गांधी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाकर पार्टी को शर्मिंदा कर दिया है, जबकि राजीव गांधी ही अय्यर को राजनीति में लाए थे।

एक वीडियो में अय्यर ने कहा कि कई लोगों ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने पर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि राजीव गांधी एक पर्यटन पालतू थे और दो बार फेल हो चुके थे। अय्यर ने कहा, “राजीव गांधी को शैक्षणिक रूप से संघर्ष करना पड़ा था। वो कैम्ब्रिज तक में फेल हो गए थे, जहाँ पास होना तुलनात्मक रूप से आसान था। फिर वो इम्पीरियल कॉलेज लंदन गए और वहाँ भी फेल हो गए। इस बात को लेकर कई सवाल हैं कि अपने इस अकैडमिक रिकॉर्ड के साथ वे प्रधानमंत्री कैसे बने। इस बात से पर्दा हट जाने दो।”

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ मणि शंकर अय्यर ने यह सवाल भी उठाया कि शिक्षा की दृष्टि से इतने कमजोर व्यक्ति को देश का प्र.मंत्री कैसे बनाया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी ने ही मणि शंकर अय्यर को राजनीति में एंट्री दी थी तथा उन पर पूरा विश्वास किया था।

■ भाजपा, राजीव के नज़दीकी सलाहकार की इन टिप्पणियों से काफी खुश हैं, क्योंकि अब भाजपा के लिये अपने नेता मोदी की शैक्षणिक योग्यता को मुद्दा बनाने वार्ता को जवाब देना और आसान हो गया है।

■ कांग्रेस ने जरूर अय्यर की टिप्पणियों को फिज़ूल की बात बताया और कहा, अय्यर अब एक कुण्ठित नेता हैं, जिन्हें पार्टी अब काफी समय से महत्व नहीं दे रही है।

■ कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने कहा, परीक्षा में फेल होना या उत्तीर्ण होना राजनीति की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, राजीव गांधी राजनीति में देश के सफल नेताओं में सदा गिने जायेंगे, क्योंकि पाँच साल में उन्होंने जो देश के लिये हासिल किया, शायद ही कोई ऐसा कर पाया है या कर पायेगा।

‘ट्रम्प की विदेश नीति में स्थायित्व या सिद्धांत नज़र नहीं आ रहा’

इस परिस्थिति में भारत की तत्कालिक चिंता है, कब अमेरिका फिर अपनी विदेश नीति बदलते हुए, पाकिस्तान की ओर झुकने लगेगा

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मार्च। कई अन्य देशों की तरह, भारत के भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मित्रता के दिन खत्म हो गए हैं। कोई भी देश, जिसका अमेरिका के साथ कोई भी लेना-देना है, बहुत अनिश्चित है और उसे अमेरिका के वादों और कमिंटमेंट्स में विश्वास नहीं है। वे यादे एक मिनेट के नोटिस पर या बिना नोटिस के भी पलट जा सकते हैं।

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है विदेश नीति में इन परिवर्तनों के कारण अमेरिका-पाकिस्तान के प्रति रणनीतिक झुकाव की पुरानी रणनीति पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

किसान नेता डल्लेवाल के अनशन के सौ दिन पूरे हुए

हिसार, 05 मार्च। हरियाणा के हिसार जिले में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के 100 दिन के आमरण अनशन के समर्थन में किसानों ने बुधवार को एक दिवसीय सांकेतिक अनशन किया। यह अनशन जिला सचिवालय और नारनौद के उप मंडलाधीश कार्यालय के सामने आयोजित किया गया। ज्ञातव्य है कि यह आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा है। किसान आंदोलन को दूसरी लहर 13 फरवरी 2024 से खनौरी बाँडर पर

■ किसानों का कहना है कि सरकार डल्लेवाल की सेहत की चिंता तो जता रही है पर लिखित वादों से मुकर रही है।

शुरू हुई थी। डल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी कानून को जल्द लागू करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि सरकार एक तरफ डल्लेवाल की सेहत की चिंता जता रही है। वहीं दूसरी तरफ बातचीत के लिए सरकार लंबी तारीखें दे रही है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार अपने लिखित वादों से मुकर रही है। उन्होंने मांग कि अगर सरकार वाकई डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंतित है, तो उन्हें तुरंत किसानों की मांगें पूरी करनी चाहिए।

‘अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो या व्यापार युद्ध या किसी और तरह का युद्ध, तो हम अंतिम क्षण तक लड़ने को तैयार हैं’

चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता लिन जियान ने न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में बहुत कड़ा जवाब दिया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 मार्च। शेष विश्व के साथ “टैरिफ वॉर” की अमेरिका की एकतरफा धमकी पर साहसिक प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा है कि अमेरिका चीन से आयोजित माल पर टैरिफ बढ़ाने के लिए फैनटेनाइल (एक नशीली ड्रग) का झूठे बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वह टैरिफ वॉर हो या ट्रेड वॉर, बीजिंग आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मंगलवार को न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। उनसे अमेरिका द्वारा चीनी आयात पर शुल्क में दस प्रतिशत वृद्धि किए जाने पर सवाल किया गया था।

उन्होंने कहा कि फैनटेनाइल मुद्दा चीनी आयात पर अमेरिकन शुल्क बढ़ाने का बहाना मात्र है। हमारे अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए हम जो कदम उठाएंगे, वे पूरी तरह

■ जैसा कि विदित है, अमेरिका ने चीन से अमेरिका को जाने वाली अधिकतर वस्तुओं पर 10 प्रतिशत और टैरिफ लगाने की घोषणा की है।

■ साथ ही चीन ने भी प्रत्युत्तर में अमेरिका से चीन को निर्यात किये जा रहे सामान: चिकन, गेहूँ, कपास आदि पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।

■ चीन की इस आक्रामक जवाबी कार्यवाही की तुलना में भारत का रुख काफी नरम तथा “एडजस्ट” करने का रहा। जैसा कि ज्ञातव्य ही है, अमेरिका 2 अप्रैल से “रैसिप्रोकल टैरिफ” लगाने की घोषणा लागू करने की बात कह ही चुका है। अतः भारत के पास चार सप्ताह से भी कम समय बचा है, अमेरिका द्वारा लगाये गये “टैरिफ” को एडजस्ट” करने के लिये। अगर अमेरिका से भारत को निर्यात किये गये सामान पर भारत ने वर्तमान “टैरिफ” चालू रखा तो अमेरिका भी भारत से अमेरिका को निर्यात वस्तुओं पर उतना ही “टैरिफ” लगायेगा और भारत का व्यापार चौपट हो सकता है।

तथा दबाव डाल रहा है। हमने उनकी मदद की, इसके लिए वो हमें दंडित कर रहे हैं। इससे अमेरिका की समस्या हल

चीन के प्रवक्ता ने आगे कहा, “हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। डराने-धमकाने की नीति हम पर नहीं चलेगी। दबाव, डर और धमकी चीन से डील करने का सही तरीका नहीं है। अगर अमेरिका सही मायने में फैनटेनाइल मसले को हल करना चाहता है तो चीन के साथ बराबरी के स्तर पर वार्ता की जाए। अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे टैरिफ वॉर हो या ट्रेड वॉर हो या किसी भी प्रकार का वॉर हो, हम आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं।”

सी.एन.एन. के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन द्वारा चीनी आयात पर शुल्क दस प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के बाद चीन ने यह प्रतिक्रिया दी है।

जवाबी कार्यवाही करते हुए चीन ने भी अमेरिका से आने वाले सामान, जैसे चिकन, गेहूँ, मक्का और कपास पर टैरिफ 15 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, सोयाबीन, पोर्क, बीफ, एक्वीटिक उत्पाद, फल, सब्जी व डेयरी उत्पादों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है।

अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दो अप्रैल से रैसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी।

फरवरी में वॉशिंगटन में ट्रम्प तथा भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देश इस वर्ष अक्टूबर तक कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले भाग पर चर्चा के लिए मान गए थे।

मोदी की ट्रम्प से मिशन 500 की घोषणा की थी, जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुँचाना है। नई दिल्ली ने एक कमेटी गठित की है, जो भारत-यूएस ट्रेड पर रैसिप्रोकल टैरिफ के प्रभाव का अध्ययन करेगी। वाणिज्य मंत्रालय की इस कमेटी में कृषि, खाद्य संवर्धन, भारी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ट्रम्प ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत की उच्च शुल्क दरों की ओर इशारा किया और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संख्या बढ़ने का लाभ मिल सकता है।

उनके द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय मीटिंग को सम्बोधित करते हुये, उन्होंने परिसीमन की कवायद पर जोरदार प्रहार किये और कहा कि यह साफ तौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने दक्षिण भारतीय अन्य राज्यों के नेताओं से इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिये एकजुट होने की अपील की।

स्टालिन की अध्यक्षता में हुई इस सर्वदलीय मीटिंग ने केन्द्र से विधिवत रूप से अनुरोध किया कि 2026 के बाद अगले 30 साल तक लोकसभा की सीटों की संख्या तथा संवैधानिक सीमाएं यथावत रखी जायें। उन्होंने कहा कि 84 वें संविधान संशोधन ने 2026 तक उक्त (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बोफोर्स : सीबीआई ने अमेरिका से हर्शमैन को ढूढने की अपील की

नई दिल्ली, 05 मार्च। बोफोर्स घोटाला मामले से जुड़ी जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने अमेरिका को रोगेटरी पत्र भेजा है, जिसमें अमेरिका से निजी जाम्स माइकल हर्शमैन को ढूढने और उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। ज्ञातव्य है कि माइकल हर्शमैन ने एक न्यूज चैनल पर दावा किया था कि वो 64 बोफोर्स तोप घोटाले की जांच में मदद कर सकता है। भारत में बोफोर्स घोटाला 1980 के

■ माइकल हर्शमैन ने एक न्यूज चैनल में दावा किया था कि वह बोफोर्स जांच में मदद कर सकता है।

दशक में सामने आया था और दौरान तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर घोटाले के आरोप लगे थे। दिल्ली की अदालत के आदेश पर अक्टूबर 2024 में अमेरिका को रोगेटरी पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पत्र अमेरिकी नागरिक के टीवी इंटरव्यू को जांच का आधार बनाया गया है। प्रशासनिक स्वीकृतियों के कारण इसे पूरा होने में 90 दिन लग सकते हैं। दिल्ली की अदालत ने सीबीआई के आवेदन को स्वीकार किया है। इसके बाद अमेरिका की न्यायिक प्राधिकरण को पत्र भेजा गया है।

‘सवा साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ’

जयपुर देहात (दक्षिण) के नागरिकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल का बजट सौगातों के लिए आभार जताया

जयपुर, 5 मार्च। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर बजट सौगातों के आभार प्रदर्शन के लिए जयपुर देहात (दक्षिण) से आए प्रतिनिधिमंडल की आभार सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की आधारशिला है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, कृषि, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनेक प्रावधान किए गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि जयपुर के विस्तार के साथ, आस-पास के इलाकों में सुख-सुविधाओं के विस्तार के लिये बजट में अनेक प्रावधान किये गये हैं।



जयपुर देहात (दक्षिण) की ओर से आए प्रतिनिधिमंडल ने बजटीय घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया। इस अवसर पर आमजन ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

बजट किसानों को आगे रखते हुए बनाया गया है। युवाओं के लिए भी सवा लाख पदों पर सरकारी भर्तियाँ और डेढ़ लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय हुए पेपरलीक प्रकरणों से राज्य का युवा परेशान था। हमने आते ही इन प्रकरणों में लिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की। हमारे सवा साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं

हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे अपराध मुक्त राजस्थान की दिशा में उठाए गए कदमों से राज्य में गैंगवार और अपराध भी कम हुआ है।

शर्मा ने कहा कि हमने प्रदेश में पानी और बिजली को प्राथमिकता पर रखा। बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्य योजना पर काम कर रही है। हमारी सरकार वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही, राज्य को

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर का विस्तार होने के साथ ही, इसके आसपास के इलाकों का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुख-सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान ‘एक ही लाल, भजनलाल भजनलाल’ और ‘दमदार मुख्यमंत्री, दमदार फैसले’ जैसे नारों से पूरा पाण्डाल गुंजायमान हो उठा तथा

लोगों ने अभूतपूर्व बजटीय घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का तहे दिल से स्वागत किया। उपस्थित आमजन ने मुख्यमंत्री को 100 मीटर लम्बा साफा पहनाया और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान जयपुर देहात (दक्षिण) के जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, पूर्व मंत्री कन्हैया लाल, बृथ मण्डल एवं जिला पदाधिकारी सहित, बड़ी संख्या में आमजन मौजूद थे।

‘राजीव गांधी शिक्षा की दृष्टि ...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कांग्रेस ने जहाँ अय्यर की टिप्पणियों को खारिज किया है और राजीव गांधी को भारत के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक बताया है, वहीं भाजपा ने अय्यर की टिप्पणियों का पूरा लाभ उठाया है। पार्टी के आई.टी. सेल के अमित मालवीय ने व्यापक रूप से उक्त वीडियो को शेयर किया है। वीडियो देखकर यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह कहाँ

शुट किया गया था। अय्यर की टिप्पणियों ने भाजपा को विपक्ष के सवालियों के विरुद्ध बोलने के लिए खूब मसाला दे दिया है, जो (विपक्ष) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्रियों को लेकर सवाल उठाता रहता है। अस्सी के दशक के मध्य में राजीव गांधी के निकट सलाहकारों में एक माने जाने वाले, अय्यर पार्टी नेतृत्व द्वारा अपनी निरंतर उपेक्षा के कारण काफी

क्षुब्ध और नाराज़ हैं। पूर्व में उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसका शीर्षक था, “द राजीव गांधी आई न्यू-द फादर ऑफ इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन”। कांग्रेस ने यह कहते हुए अय्यर की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है कि “पार्टी में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और उनके पास पार्टी का कोई महत्वपूर्ण पद भी नहीं है। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने कहा, “उनके वक्तव्य पर

अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।” पार्टी के वरिष्ठ नेता, तारिक अनवर ने कहा कि अच्छे से अच्छे लोग भी स्कूल और कॉलेज एजाम में फेल हो जाते हैं। लेकिन राजीव गांधी राजनीति में फेल नहीं हुए। जब उन्हें जिम्मेवारी दी गई और वे प्रधानमंत्री बने, मेरा मानना है कि देश में बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सिर्फ पाँच सालों में इतना कुछ हासिल कर लिया।

‘अगर अमेरिका ...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा, भारत हम पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाता है, यह सिस्टम अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, कभी भी नहीं था।

उन्होंने “अमेरिका फस्ट” की नीति पर जोर देते हुए कहा, “अन्य देश कई सालों से हम पर टैरिफ लगा रहे हैं, अब हमारी बारी है। हम भी उनके खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल करेंगे।”

प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स, जिनमें कैनडा, मैक्सिको, चीन, युरोपियन यूनियन और भारत शामिल हैं, को नई टैरिफ नीति में निशाना बनाया जाएगा। यह टैरिफ अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में भारी बदलाव करने की नीति का प्रमुख अंग है।

ट्रम्प हमेशा से मानते हैं कि ग्लोबल ट्रेड रूल्स अमेरिका के लिए नुकसानदेह हैं और इसलिए वे रैसिप्रोकल टैरिफ पर जोर दे रहे हैं, अपने पहले कार्यकाल में, उनके प्रशासन ने ऐसे ही फैसले किए थे, पर, उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया था।

नया टैरिफ शुल्क देश के आधार पर लगाया जाएगा। इसमें सिर्फ शुल्क दर को ही नहीं बल्कि अन्य व्यवधानों पर भी ध्यान में रखा जाएगा।

‘ट्रम्प की विदेश नीति में स्थायित्व ...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

न लौट जाए और उसे अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई फिर न शुरू कर दे। अमेरिकन कांग्रेस के अपने भाषण में ट्रम्प ने एक खतरनाक आतंकवादी को संपने के लिए पाकिस्तान का आभार जताया। यह आतंकी काबुल हवाई अड्डे पर हुए बम विस्फोट में शामिल था। इस घमाके में अफगान नागरिकों सहित, 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जो अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान छोड़ने की घोषणा के बाद लौट रहे थे।

ट्रम्प ने अपने भाषण में यह भी बताया कि अमेरिका की खुफिया सेवा का एक सैनियर अफसर पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. के मुखिया से मिला और आतंकी को अमेरिका के सुपुर्द करने के मुद्दे पर काम किया, वह इस सप्ताह के अंत तक अमेरिका लौटने वाला है। इसी भाषण में उन्होंने अन्य देशों के साथ भारत को कोसा और अमेरिकन कारों पर ज्यादा टैरिफ के लिए भारत की आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत, अमेरिकन कारों पर शत-प्रतिशत टैरिफ लगाता है। ट्रम्प, आदतन फैक्ट चैक नहीं करते हैं और डेटा व तथ्यों के बारे जरा भी परवाह नहीं करते हैं।

असल में वर्तमान में भारत आयातित लज्जरी कारों पर 70 प्रतिशत टैक्स लेता

है, चाहे वह किसी भी देश से क्यों न हों, मोटर बाइक पर 40 प्रतिशत टैरिफ लगाता है। ट्रम्प ने पूर्व में हाली वीडियोस मोटर बाइक और इन पर लगे टैरिफ का मुद्दा उठाया था। इसके बाद भारत ने मोटर बाइक से आयात शुल्क घटाया था। ट्रम्प डेटा और तथ्यों की परवाह नहीं करते हैं और अपनी ही सोच पर चलते हैं।

इसका नतीजा यह है कि अमेरिका अब जो करेगा, वो पूर्णतया अनिश्चित है। अमेरिका के विश्वस्तमित्र, जो कई दशकों से अमेरिका के साथ थे, अब अमेरिका का विकल्प तलाश रहे हैं। ताईवान दशकों से अमेरिकन सपोर्ट पर आश्रित था, पर अब अमेरिका का विकल्प ढूँढ रहा है। ताईवान, चीन से अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर था। डॉनल्ड ट्रम्प के एक्शन प्रतिशोधात्मक और विनाशकारी साबित हो रहे हैं। ट्रम्प ने ब्रिटेन को आदेश दिया है कि इटैलीजैस जानकारी किसी को न दी जाए, इस पर तुरंत अमल हो। अमेरिका ने यूक्रेन को भी गुप्तचर जानकारी देना रोक दिया है जो कि यूक्रेन की सैन्य कार्यवाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका सहयोगी देशों को भी गुप्तचर जानकारी नहीं दे रहा है। इस भ्रम और तनाव के बीच एक देश है, जो अमेरिका की बात नहीं मान रहा है और अमेरिका के पास इसका विकल्प नहीं है।

अमेरिका के बढ़े हुए शुल्क का सामना कर रहे चीन की संसद ने शी जिनिपिंग की अध्यक्षता में मौजूदा वर्ष के लिए अपनी आर्थिक योजना को अंतिम रूप दिया। ट्रम्प द्वारा लगाए गए शुल्क व तमाम धमकियों के बावजूद चीन ने 5 प्रतिशत ग्रोथ टारगेट निर्धारित किया है। इसके अलावा, अमेरिका के दण्डात्मक आर्थिक कदमों से निपटने के लिए चीन अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे उनके कामकाज तथा प्रॉफिट को नुकसान पहुँचा है। चीन ने अब अमेरिका को महत्वपूर्ण खनिजों व कच्चे माल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था व कम्पनियों को नुकसान हो सकता है। कुछ बेहद महत्वपूर्ण खनिजों का कुल 85 प्रतिशत चीन के आधिपत्य में है। ये पदार्थ रक्षा उद्योग व ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका, यूक्रेन से यह पदार्थ हासिल करना चाहता है, पर जैलैस्की से विवाद के बाद यह योजना विफल हो गई है। ट्रम्प ने वादा किया है कि वे यह पदार्थ ग्रीनलैंड से हासिल करेंगे, चाहे जो हो जाए। संकीर्ण दृष्टिकोण वाले ट्रम्प अमेरिका के तटों से आगे नहीं देख पा रहे हैं। वे अपने ही बनाए गड्डों में गिर सकते हैं।

बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यू.पी., ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थितियों को फ्रीज कर ही रखा है। स्टालिन ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया जना भी प्रस्तावित किया, जिसमें सभी दक्षिणी राज्यों के सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हों। यह समिति इस मामले में जनता में जागरूकता पैदा करे तथा सीटों की सम्भावित कमी को रोकने के लिये आवश्यक हो चुके संघर्ष को आगे बढ़ाये। इस संघर्ष के क्षेत्र और पहुँच को विस्तार देते हुये तथा इस प्रक्रिया में अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों को शामिल करते हुये, स्टालिन ने इस मुद्दे को सबसे ऊपर पहुँचा दिया। यह मुद्दा राज्य विधानसभा के चुनावों तक की अवधि में छाया रहेगा तथा इसके साथ तीन भाषा फॉर्मूले का विवादस्पद मुद्दा भी जुड़ा रहेगा। इस प्रकार, उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा को बिल्कुल अलग-थलग कर देने की व्यवस्था कर दी है। विशेष रूप से, अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिये अनामद्रमुक तथा भाजपा के गठबंधन की बैक-चैनल चर्चाओं की पृष्ठभूमि में, परिसीमन तथा भाषा के भावनात्मक मुद्दे को लेकर हुई अजय की मीटिंग ने उक्त दोनों

पूर्व मित्र-दलों के बीच प्रभावी रूप से अलगाव पैदा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। प्रसंगवश बता दें कि केवल भाजपा ने ही आज की इस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया था, जिसमें कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुये तथा ये प्रस्ताव तमिल और तमिलनाडु के हित में माने गये। परिसीमन सम्बंधित प्रस्ताव में, इस कार्यवाही को नाजायब बताया गया। स्टालिन द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव को सर्वदलीय मीटिंग में सर्वसम्मति से पारित कर दिया। प्रस्ताव में स्टालिन ने कहा, “चूँकि दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया, इसलिए इन राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या कम करना अनुचित है। केन्द्र को (सीटों के मामले में) 2026 के बाद के 30 वर्षों तक वर्तमान व्यवस्था यथावत रखनी चाहिये, क्योंकि वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री (अटल बिहारी वाजपेयी) ने वादा किया था कि परिसीमन का निर्णय 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा। अन्य राज्यों से भी जनसंख्या - नियंत्रण के उपायों को क्रियान्वित कराया

जाना आवश्यक है।” प्रस्ताव में भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की परिसीमन की कवायब की निन्दा भी की गई। सर्वदलीय मीटिंग के प्रस्ताव में तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिणी राज्यों के राजनैतिक प्रतिनिधित्व के लिये गंभीर खतरा बताया। स्टालिन ने कहा कि “केन्द्र की भाजपा सरकार इस मुद्दे पर लोकसभा में राज्य के 39 सांसदों की आवाज़ को सुनने तक के लिये तैयार नहीं है। हमें 2026 की जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन का साफ तौर पर विरोध करना पड़ेगा।” उन्होंने कहा, “हमें इस मुद्दे पर दृढ़ रुख अपनाना होगा।”

दक्षिण भारत के ऊपर लटकती तलवार जैसा है। यह परिसीमन 2026 की जनगणना के आधार पर होगा। अगर केन्द्र ने मौजूदा 543 लोकसभा क्षेत्र कायम रखे, तो तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व में 8 सीटें कम कर दी जायेंगी।” स्टालिन ने समझाया कि अगर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 848 कर दी गई तथा परिसीमन प्रतिशत आधार पर किया गया तो तमिलनाडु को 22 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। स्टालिन ने कहा, “लेकिन, अगर परिसीमन वर्तमान जनसंख्या के आधार पर किया गया तो तमिलनाडु को सिर्फ 10 सीटें मिलेंगी। दोनों ही तरीकों से अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन तमिलनाडु की आवाज दबा दी जायेगी। हमें इस पंडवत्र को पराजित करना है।” मीटिंग में पारित एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर सांसदों की संख्या बढ़ाई जानी है तो संविधान में ऐसा संशोधन किया जाये कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा तथा राज्यसभा में तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिणी राज्यों की सीटें आनुपातिक रूप से बढ़ाई जायेंगी।

MARUTI SUZUKI ARENA

पुरानी छोड़े, नई लाएं!

अपनी पुरानी कार स्क्रेप करें और भविष्य की ओर चलें।

ADDITIONAL SCRAPPAGE AND EXCHANGE BENEFITS UP TO ₹25 000*

01 March 2025

Fuel will not be provided to vehicles older than 15 years at petrol pumps in Delhi after March 31.

The Delhi government will stop fueling vehicles over 15 years old at city stations after March 31, according to Environment Minister Manjinder Singh Sirsa. The decision follows a meeting on air pollution, with Sirsa stressing the government's efforts to tackle vehicular emissions.



BEST SCRAPPAGE VALUE#

BEST EXCHANGE OFFERS

UPTO 100% ON-ROAD FINANCE

3 years 100 000 km WARRANTY**

विशेष ऑफर

SWIFT ₹58 100* | WAGONR ₹73 100*



SCAN TO CONNECT TO SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM

T&C apply. Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper. Offers vary across variants. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on select models/variants. Above mentioned savings amount is the value of maximum savings on select models. Offer valid with select financiers only. **3 years or 100 000 km - whichever is earlier. #Scrappage Offer valid for limited time only. For more details, please contact your nearest ARENA dealership. *Scrapage value offer is brought to you by Maruti Suzuki Toyota India Private Limited (a joint venture company between Maruti Suzuki India Ltd and Toyota Tsusho Group). Above offers are valid till 31st March 2025.

VISIT YOUR NEAREST MARUTI SUZUKI ARENA DEALERSHIP TODAY OR E-BOOK AT WWW.MARUTISUZUKI.COM | CALL 1800 102 1800